THE BUDGET (RAJASTHAN), 1967-68

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K C PANT) Sir, I beg to lay on the Table a statement of the estimated receipts and expenditure of the State of Rajasthan for the year 1967-68.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*contd.*

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिये रखा गया जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसके बारे मे यह निवेदन है कि साधारणत राष्ट्रपति जी का भाषण इस बात का द्योतक होता है कि हमारे यहा अगले वर्ष मे क्या होने वाला है। बहुत खेद के साथ मुझे कहना पडता है कि हमारी यह सरकार राष्ट्रपति जी के साथ भी मखौल करने मे नही चूकती। 1964-65 के अभिभाषण मे उन्होने यह कहा था कि ससद मे पेटेंट बिल पेश किया जायेगा और उसको पारित करेगे। परन्तु खेद के साथ कहना पडता है उपसभाध्यक्ष महोदय, कि लाखो रुपया खर्च करने के बाद भी ऐसा लगता है कि विदेशियो के प्रभाव मे आना पडा, क्योकि जो पेटेंट बिल पारित होने वाला था ट्रेजरी बेंच पर कोई मत्री तो रहना चाहिये।

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: No Minister is here.

[*At this stage the Minister of Law (Shri P. Govinda Menon) entered.*]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M P. BHARGAVA): Yes, you continue now.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : उपसभाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता लन्च अवर कर देते तो हमारे मत्री महोदय को कष्ट नही होता। खास तौर से, जितनी बड़ी फौज काग्रेस ने अपने मंत्रियो की बना रखी है उतनी होने के बाद भी इतनी डिस्कर्टसी इतना अवमान, इतना अपमान, जिसके कारण ही दो दो बार चैमरमैन महोदय ने रिमार्क पास किये उसके बावजूद भी हमारे मत्री महोदय, जब कि किसी को बोलने को कहा, तब उठ कर चल दिये। वे समझे यह लन्च अवर हो गया।

श्री शीलभद्र याजी लोक सभा मे लन्च अवर होने लगा तो प्रथम बार यहा शुरूआत हुई कि यहा खत्म हुआ। कुछ लन्च का समय तो दिया जाय।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मै कह रहा था यहा पर यह सरकार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मखौल उडाने मे नही चूकती क्योकि राष्ट्रपति जी के भाषण मे पेटेंट बिल की चर्चा तो हुई लेकिन बाद मे उसकी बात ही नही आई। 1964 एव 1966 मे भी राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण मे फसल बीमा योजना बिल का उल्लेख किया था लेकिन वह बिल 1964 मे नही आया, 1965 मे नही आया और 1966 मे नही आया, 1967 मे नही आया। इसी तरह से 1965 के अभिभाषण मे उन्होने बतलाया था कि आल इण्डिया हैण्डलूम बोर्ड पर एक बिल आयेगा, वह आया मगर लैप्स हो गया। 1966 मे राइस बिल से सम्बन्धित बिल के बारे मे रेफरेन्स दिया था, वह आया लेकिन वह भी लैप्स हो गया। इसलिये मै प्रार्थना करूगा कि कम से कम राष्ट्रपति महोदय के मुख से गलत बात कहलाने का कष्ट न किया करे।

श्रीमन्, चतुर्थ आम चुनाव के बारे में हमारे राष्ट्रपति महोदय ने साधारणत. उसको ठीक बताया, कुछ हिंसा और उपद्रवों की घटनाओ की चर्चा करके। मगर आश्चर्य है

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया] उपसभाध्यक्ष महोदय, कि इस चुनाव में जो हिंसा और उपद्रव की घटनाएं घटी वह बहुत खेदजनक हुई । प्रधान मंत्राणी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वह बहुत निन्दनीय है ही, मगर विरोधी दल के सदस्यों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी भी उतनी ही निन्दा करनी पड़ती है । रायपुर में जन संघ के कार्यकर्त्ता की हत्या कर दी गई । बिलासपुर मे विधान सभा के सदस्य पद के उम्मीदवार के ऊपर गोली चलाने का प्रयास किया गया । स्वय मेरे ऊपर पाद्रना में पत्थर फेंके गए, पत्थर मुझको लगते लगते रह गया और दूसरे के ऊपर लगा । इसी तरह से एक गाव में मुझे जिन्दा जलाने की योजना बनाई गई थी पर बीच मे ही वह समस्या किसी तरह हल हो गई । वहां इस चुनाव के दौरान में जो दुर्घटनाएं घटी, वे ठीक नही कही जा सकती ।

सत्तारूढ़ दल द्वारा सत्ता का जो दुरुपयोग किया गया उसमें कई कर्मचारियों ने जो सक्रिय सहयोग दिया वह बहुत निन्दनीय है । हमारे रायपुर जिले के कलक्टर श्री भावे ने तो कांग्रेस उम्मीदवार के इलेक्शन एजेंट को भी मात कर दिया क्योंकि इलेक्शन एजेंट के पास कोई सत्ता नही थी लेकिन वे सत्ता के बल पर काम करते थे । तो हमारे यहां रायपुर के कलेक्टर श्री भावे ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग इतना अधिक किया कि जिसका उदाहरण हमारे माननीय महन्त जी ने अपने भाषण में दिया, कि उनको कम से कम सात लाठिया खानी पडी । इसी तरह इससे घृणित काम और क्या हो सकता है कि लोगो को राहत पहुंचाने के नाम पर जो धन खर्च होना था वह धन वहा खर्च हुआ जहा पर मुख्य मत्री चुनाव लड़ रहे थे, जहा पर वहा के राजस्व मंत्री चुनाव लड रहे थे और यहा के स्टेट मिनिस्टर श्री शुक्ल चुनाव लड रहे थे । उन क्षेत्रों में विशेष रूप से वह रकम अधिक खर्च की गई और अकाल के नाम पर जो रकम खर्च की जाने वाली थी उसको चुनाव में उपयोग करने का प्रयत्न किया । इतना ही नही उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे यहा शासकीय कर्मचारियो को चुनाव मे कांग्रेस को जिताने के लिये काफी इन्स्ट्रक्शस, सूचनाये दी गई और उनका उपयोग किया गय । राजस्थान में भी बार्डर रोड बनाने के काम का ठेका देते वक्त लोएस्ट टेन्डर का खयाल नही किया गया और जिस ठेकेदार ने स्वीकार किया कि वह चुनाव के दिनों में काग्रेस के कैन्डिडेट को जिता देगा उसका ठेका मंजूर किया । इतना ही नही , उनको जीप खरीदने के लिये, ट्रक के नाम पर, रुपया भी उधार दिया गया । जिस ठेकेदार ने वह जीप खरीदी उसने वह जीप कांग्रेस के उम्मीदवार को दे दी । तो इस प्रकार यह जो चुनाव हुए है, मुख्यत. मध्य प्रदेश के चुनाव में, उनमें काग्रेस के दल ने आतंक का और सत्ता का दुरुपयोग किया । रेप्रेजन्टेशन आफ द पीपुल एक्ट में जितने भी करप्ट प्रैक्टिसेज की संज्ञाएं दी हैं, कही एक, कही दो इससे भी ज्यादा का उपयोग लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा है । इसको हम उचित नहीं समझते ।

यह तो हुआ ही, इसके साथ साथ जब जम्मू और काश्मीर के चुनाव की बात हम सुनते है और विचार करते है कि प्रजातन्त्र में इस तरह की दुर्घटनाएं घटें तो यह प्रजातन्त्र के नाम पर भीषण कलंक लगता है । इसकी विशेष चर्चा इसलिए नही करना चाहता क्योंकि लोक सभा में उस पर काफी कहा जा चुका है । अखबारो में भी इसकी काफी चर्चा हो चुकी है । मैं तो केवल एक निवेदन करूंगा कि प्रजातन्त्र की यह मूलभूत माग है कि हमारी सरकार जम्मू और काश्मीर में जितने वर्तमान चुनाव हुए है उन सबको निरस्त कर दे । एकदम बीस बीस चुनाव के नामजदगी पत्र खारिज हो जाये और कई कैन्डिडेट्स निर्विरोध चुन कर आ जाये, जहा जरा से वोट पड़े है वहा 90 परसट तक मतदान हुए यह बता देना

ये सारे जो करिश्मे काश्मीर मे हुए है वे निन्दनीय है और इसलिए मैं प्रार्थना करूगा कि हमारे शासन को अभी इन सारे निर्वाचनो को निरस्त करा के पुन निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिये ।

हमारे देश मे खाद्य का सकट बहुत भीषण है । खाद्य के सकट के बारे मे आज से नही, शुरू से ही राष्ट्रपति जी के भाषणो में बराबर उल्लेख होता आया ह । जनवरी, 1950 मे उन्होने कहा था ।

"मेरी सरकार ने घोषित किया है कि हम खाद्यान्न की कमी को 1951 के अन्त तक पूरी कर लेगे ।"

अब 1951 की बजाय 1967 आ गया है पर ज्यो ज्यो दवा की, मर्ज बढता ही गया । 31 जुलाई 1952 को उन्होने कहा था

"खाद्यान्न की समस्या को हमारी सरकार उच्चतम प्राथमिकता देती रहेगी ।"

6 अगस्त 1951 को राष्ट्रपति जी ने कहा .

"मेरी सरकार के सामने खाद्यान्न समस्या गम्भीरतम है । हमारे बडे क्षेत्र पर अकाल की छाया है विशेषत बिहार मे ।"

ता० 5-2-52 को फिर उन्होने कहा

" 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अच्छे परिणाम हो रहे है । मेरी सरकार एक कमेटी का निर्माण कर रही है जो 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के कार्य की जाच कर सिफारिश करेगी ।"

फरवरी 1958 मे उन्होने कहा था ।

"खाद्यान्न का उत्पादन बढाने के समस्त प्रयास किये जा रहे है । यह आवश्यक है कि खाद्यान्न के मामले मे स्वावलम्बी हो ।"

फरवरी 9, 1959 मे उन्होने फिर कहा

"खाद्यान्न के मामले मे स्वावलम्बी होना ही एकमात्र सन्तोषजनक हल होगा ।"

मार्च 1962 मे उनका कहना था

"हमारा उद्देश्य केवल अनाज मे आत्मनिर्भर होना ही नही बल्कि निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा सग्रह करने तथा बढते हुए उद्योगो के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने के लिये व्यापारी पैदावार को बढाना भी है ।"

तो इस दृष्टि से यह खाद्य सकट कभी बहुत ज्यादा हो जाता है कभी हलका भी हो जाता है मगर सकट कायम है । इस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भी जनता को भुलावे मे डालने का प्रयास किया जा रहा है—यह कई तरह के भाषण अभिभाषणो मे उनके द्वारा उल्लेख है । हमारे पाटिल साहब तो लोक सभा मे बोल चुके हैं 14 मार्च 1952 को

"हम तृतीय पचवर्षीय योजना पूरी होने के पूर्व ही खाद्यान्न के मामले मे स्वावलम्बी हो जायेगे ।"

उसके बाद उन्होने वाशिगटन मे 30 मई 1963 को कहा था

"1971 मे हमारा देश पूरी तौर पर खाद्यान्न के मामले मे स्वावलम्बी हो जायेगा ।"

फिर उसके बाद वे कहते है 26 जून 1963 को

"पाच छ साल के अन्दर हम गेहू के मामले मे स्वावलम्बी हो जायेगे ।"

फिर 29 सितम्बर 1963 को वे कहते है

"दस साल मे हमारा देश स्वावलम्बी हो जायेगा ।"

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया]

इस तरह से लोगो को भुलावे मे डाल कर यदि हमारी सरकार समस्याओ का हल समझती है तो वह बिल्कुल उचित नही। मै प्रार्थना करूगा कि यह जो अभी तक की हमारी खाद्य नीति चल रही है इस बात को जानते हुए भी कि हमारे देश मे खाद्य सकट है उसको हल करने के लिये अन्य कारगर प्रयास को छोड कर इधर उधर के बहाने करना यह उचित नही है। खाद्य सकट को हल करने के लिए कई विदेशी यहा आए, कई कमेटिया बन गई, कई प्रकार के बीज आए—कुछ बीज उगे ही नही, अनाज पैदा नही हो पाया—वर्णशकर बीज पैदा किया और अन्त मे मर्ज बढता गया ज्यो ज्या दवा की।" आज हमारे देश मे खाद्य सकट बढता जा रहा है। हमारे जो विदेशी मित्र आते है वे उनके देश की परिस्थिति के अनुसार चर्चा करते है लेकिन विदेशो पर निर्भर रहने वाली योजनाए कभी हमारे काम नही आएगी। हमारी सरकार का प्रारम्भ से लक्ष्य रहा है कि सारी खेती ट्रैक्टर्स से होनी चाहिये, माडर्न इम्प्लीमेन्ट्स प्रयोग मे लाये जाने चाहिये विदेशी बीज, विदेशी खाद प्रयोग मे लाई जानी चाहिये। मै जानना चाहता हू मत्री महोदय से कि क्या इस विदेशो पर निर्भर रहने की नीति के परिणामस्वरूप हम कई मामलो मे पीछे नही रह गये है? यदि खाद्यान्न पैदा करने मे भी हम विदेशो पर निर्भर करते रहे तो हम कभी भी स्वावलम्बी नही हो सकते। हमारे यहा करोडो की पूजी ट्रैक्टर्स मे लगी हुई है जिनके स्पेयर पार्ट्स नही मिल रहे है हम जब तक विदेशी खाद नही पाते हम अपने यहा अनाज पैदा नही कर सकते यह हमारी धारणा है। मै प्रार्थना करूगा खाद्य सकट को हल करने की हमारी नीति ऐसी होनी चाहिये कि हमारा देश उस मामले मे स्वावलम्बी रहे। यदि ट्रैक्टर के आधार पर खेती प्रारम्भ कर दी और उसका डीजल आयल क्रूड आयल ईरान मे रह गया तो हम अपने यहा ट्रैक्टर्स चला कैसे सकेंगे। इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे यहा खाद्य सकट को हल करना है तो हमारी योजना हमारे देश मे जो सामग्री उपलब्ध है जो साधन है, उन्ही पर आधारित होनी चाहिये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर के पहले जो सब से आवश्यक चीज थी वह सिचाई की थी। सिचाई की सुविधा जितनी हमारे किसानो को दी जानी चाहिये थी वह नही दी गई। हमारे विदेशी सलाहकारो ने चम्बल बाध और भाखडा बाध बनाने तथा अमुक अमुक बाध बाधने की सलाह हमारी सरकार को दी ताकि इन बाधो द्वारा नहरे निकाली जा सके लेकिन देखने मे यह आया कि इन बाधो से कोई ज्यादा फायदा हमारे किसानो को नही पहुचा और न ही इन बाधो के द्वारा बिजली की पूरी सप्लाई की जा सकी। हमारे भारत वसुधरा के गर्भ मे पानी छिपा हुआ है लेकिन हमारी सरकार ने उसको निकालने का अच्छा प्रयत्न नही किया ताकि यह पानी सिचाई के काम आ सकता। इस ओर हमारी सरकार प्रयत्नशील नही हुई। हमने ऐसी ऐसी योजनाए बनाई जिस से हम आसमान की तरफ ज्यादा निर्भर रहे। हम चाहते है कि सरकार आसमान की तरफ देखना छोड दे और वह जमीन की तरफ देखे। जिस जमीन पर हम चलना चाहते है, जिस जमीन पर हम कृषि की पैदावार बढाना चाहते है, उसके ही गर्भ मे पानी छिपा हुआ है। इसलिये हमे इस तरह की योजना बनानी चाहिये जिस से हर खेत की जमीन पानी से सिचित हो सके। अगर हम इस तरह का लक्ष्य अपने सामने रखेगे तो हमे बहुत समय तक विदेशो पर निर्भर रहने की आवश्यकता नही रहेगी। लेकिन हमारी सरकार का यह रवैया है कि मर्ज कुछ है और इलाज उसका कुछ किया जाता है और इसका नतीजा यह होता है कि ज्यो ज्यो इलाज किया मर्ज भी बढता ही चला गया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि

सब से अधिक लक्ष्य इस बात का रखना चाहिये कि हर गाव मे जो खेती के लायक जमीन है उसमे कुए बनाये जाय ताकि उसके पानी से सिचाई की व्यवस्था हो सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपनी खाद्य नीति से देश मे ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हमारे यहा जो अनाज उत्पादन होता है उसका वितरण विचित्र तरीके से किया जाता है। अक्सर देखने मे यह आता है कि एक जगह पर तो अनाज बहुत मात्रा मे है, सडता रहता है और दूसरी जगह पर उसी अनाज के लिए लोग भूखे मरते है। इस तरह की स्थिति विदिशा और कोटा मे देखने मे आई। वहा पर कई स्थानो पर तो अनाज सड रहा है क्योकि हमारे वितरण की व्यवस्था ही ऐसी है कि वह अनाज दूसरी जगह नही जा सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि हमारे जो खाद्य के जोन्स है उनको समाप्त किया जाना चाहिये। जहा तक अनाज के वितरण का सबध है सारे देश को एक इकाई मानकर तथा सारे देश की जनता को खाना खिलाना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है इस दृष्टिकोण को सामने रखकर हमे सब जोन्स को समाप्त कर देना चाहिये। जहा पर अनाज की कमी है वहा पर अनाज पहुचाया जाना चाहिये। जब तक हम जोन्स की प्रथा को बद नही करते तब तक हमारे वितरण की व्यवस्था मे सुधार नही हो सकता है और न ही यह समस्या ही हल हो सकती है।

वितरण व्यवस्था और जो हमारे देश मे खाद्य के जोन्स बने हुए है उन से हमारी सरकार को भ्रष्टाचार करने का अवसर मिल गया है। हमारे मध्य प्रदेश मे खाद्य मत्री श्री गौतम शर्मा ने लाखो रुपया बनाया। उन्होने गुलाबी चने और मूगे आदि का परमिट देकर लाखो रुपया इकट्ठा किया और इस बात को लेकर लोग जोर जोर से चिल्लाकर कहते है कि जो गुलाबी चने का डील हुआ है उसमे हमारे खाद्य मत्री ने लाखो रुपया बनाया है। मै चाहूगा कि हमारे मत्री जी इस बारे मे जाच करे कि हमारे मत्रियो और दूसरे कर्मचारियो ने जो भ्रष्टाचार किया है वह कहा तक उचित था। जब कोई गरीब आदमी एक किलो अनाज ले जाता है तो उसको रोका जाता है और दूसरी तरफ रिश्वत लेकर ट्रक के ट्रक अनाज भरकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते है।

हमारे किसानो पर आजकल जो अत्याचार हो रहा है उसको बद करना होगा। उनके ऊपर जो लैवी सख्ती मे लगाई गई है उसको बद करना होगा। आज हालत यह है कि किसानो के पास जो बीज के लिए अनाज होता है और अपने खाने के लिए जो अनाज होता है उस तक को जबर्दस्ती सरकारी कर्मचारी लैवी के नाम पर उठा ले जाते है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस तरह के जो अत्याचार हमारे किसानो के ऊपर हो रहे है वे बद किये जाने चाहिये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, निकट भविष्य मे हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद तथा योजना आयोग के पुनगर्ठन की राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मे चर्चा की गई है। उन्होने स्पष्ट कहना चाहिये था कि इसमे विशेषज्ञो को ही रखा जायेगा और इन्हे राजनैतिक पुनगर्ठन का अखाडा नही बनने दिया जायेगा।

हमारी सरकार अवमूल्यन के बाद यह कहती थी कि इस से हमारे रुपये की साख मजबूत होगी विदेशी मुद्रा अधिक मिलेगी, निर्यात व्यापार बढेगा। लेकिन मै यह कहना चाहता हू कि अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप 5 जून 1966 को हम पर कर्जा 27,33,86,53,000 रुपया था और 6 जून, को वह कर्जा 41 02 57,49,000 रुपया हो गया। इसी तरह से अतराष्ट्रीय सस्थान मे जमा रकम मे हम ?,03,60,79,000 रुपया देना था। इस बारे मे सरकार ने यह दलील दी थी कि इतना नकसान होने के बाद

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया] भी हमारा विदेशी व्यापार बढ़ेगा और हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। मगर इन सारी कल्पनाओं से और इन सारे विचारों से यह सारी योजना खोखली साबित हुई। अभी 6 महीने पहले जो हिसाब मिला जून से दिसम्बर, 1966 की तुलना में जून, से दिसम्बर 1967 तक उसके मुताबिक 12, 96,14,000 डालर की विदेशी मुद्रा कम आई। इस व्यापार ने यह प्रमाणित कर दिया है कि केवल हमारी मुद्रा का ही अवमूल्यन नहीं हुआ वरन् हमारे कांग्रेस दल में बैठी मुद्राओं की बुद्धि का भी अवमूल्यन हो गया है। हमारी सरकार ने अवमूल्यन के समय कहा था कि इस से हमारा निर्यात व्यापार बढ़ेगा, मगर वह नीति गलत साबित हुई। यह खुशी की बात है कि श्री मोरार जी देसाई ने कहा है कि अब आगे अवमूल्यन नहीं होगा।

जहां तक विदेश नीति का सवाल है वह इतनी अच्छी है कि इस समय हमारा निकटतम अंतरंग मित्र इस संसार में कोई नहीं है। हमारे मित्र इजरायल ने हमारे साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया था, लेकिन हमारी सरकार ने उसका कोई समादर नहीं किया। हमारी सरकार मानवीय अधिकारों की बात करती है, लेकिन चीन ने तिब्बत के ऊपर जो अत्याचार किये हैं, वहां के नागरिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये जो आन्दोलन चला रखा है, उसके बारे में राष्ट्रपति के भाषण में कोई चर्चा नहीं है। राष्ट्रपति के भाषण में वहां के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को मदद देने तथा सहयोग देने के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना था।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा और इसलिये मैंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं कि उन्हें स्वीकार किया जाय। मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्रपति के भाषण झूठे आश्वासन भविष्य में न दिलाये जायें जिन्हें कि पूरा नहीं किया जा सकता है।

श्री शिवानन्द रमौल (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण में कुछ जरूरी चीजों की तरफ संकेत किया गया है और आयन्दा वर्षों में जो होने वाली चीजें हैं, भारत सरकार को करनी हैं, उनकी तरफ इशारा किया गया है।

इस वक्त मुल्क के सामने दो ही मुख्य प्रश्न हैं। एक तो खाद्य समस्या है और दूसरी आवश्यक चीजों के रोजाना बढ़ते हुए दाम। राष्ट्रपति जी ने एक जगह अपने भाषण में यह जिक्र किया है कि सरकार के सभी कामों को ठीक ढंग से चलाने के लिये सरकारी कर्मचारियों में इन्टैग्रिटी और ईमानदारी का होना निहायत जरूरी है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह विश्वास दिलाया है कि कार्यों का पूरा न होने का कारण यही समझा जा सकता है कि जहां तक गवर्नमेंट मशीनरी का ताल्लुक है उनमें लगन के साथ, दृढ़ता के साथ कार्य करने की वृत्ति कुछ कम हो गई है।

जहां तक खुराक का सम्बन्ध है मुल्क में खुराक की पैदावार बढ़ाने के लिये कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसी संस्थायें कायम की गई थीं, लेकिन इसके बावजूद भी खाद्य समस्या के बारे में अभी तक हमारा मुल्क आत्म निर्भर नहीं हो सका। यह कहा जा सकता है और यह ठीक भी है कि अचानक कई एक चीजें हो गई हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई, चीन के साथ लड़ाई हो गई और इसकी वजह से सरकार का ध्यान इन बातों की तरफ आकर्षित हो गया तथा कुछ पैसा अधिक खर्च हो गया। इन चीजों के बावजूद भी बहुत सी चीजें इस मुल्क में ऐसी चल

रही है जो कि इस वक्त मौजूदा हालत में अनावश्यक है और जो कि लक्जरी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये चीजें निहायत आवश्यक नही है और इस तरह से वेस्टफुल एक्सपेडीचर हो रहा है जिसको बड़ी आसानी के साथ रोका जा सकता है। इसका नतीजा यह होगा कि इस पैसे को हम खाद्य समस्या और जो दूसरी आवश्यक चीजें है, मुल्क के सामने जो बडी बड़ी समस्याये है उनको हल करने मे लगा सकते है और वे सहायक हो सकती है।

खाद्य समस्या को हल करने के लिये खास चीजे है आबपाशी का होना, इसके साथ साथ रासायनिक खाद और दूसरी लोकल खाद का ज्यादा से ज्यादा मुहैया किया जाना। किसानो को इसेटिव दिया जाना भी निहायत जरूरी है, चाहे वह कीमतो की शक्ल मे हो या और किसी शक्ल मे हों। एक तरफ अनाज की कीमत बढ रही है और दूसरी तरफ किसानो के लिये जो और आवश्यक चीजे है, जैसे कपडा है, लोहा इत्यादि है, उनकी भी बढी हुई कीमते किसानो को देनी पडती है। तो जब तक दूसरी चीजो की कीमते नीचे नही आयेगी तब तक यह नामुमकिन है कि अनाज की कीमतो मे कमी आ सके। इन चीजो को करने के लिये मैं यह आवश्यक समझता हू कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट के अधिकारी है, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है जो हर एक काम को इम्प्लीमेंट करने के लिये जिम्मेदार है, उसकी तरफ पूरी तवज्जह दी जाय। उनमे एक ऐसी भावना, ऐसी स्प्रिट पैदा करनी चाहिये जिससे वे मुल्क की भावना से काम करे और अपने जाती मफाद को ध्यान मे रख कर सारा काम उसी पर निर्भर न करे।

इसके अलावा मै आपकी आज्ञा से अपने इस प्रदेश का मामला इस माननीय सदन के सामने और सरकार के सामने रखना आवश्यक समझूगा और वह है हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज्ड स्टेट का स्टेटस देने के बारे मे। संत फतेह सिह के मुतालिबा पर पंजाब का डिवीजन हुआ और उसमे फैसला हुआ कि पंजाब मे हिन्दी रीजन का जो पहाड़ी इलाका है वह हिमाचल प्रदेश मे मिला दिया जाय। जिस वक्त से हिमाचल प्रदेश बना है उस वक्त से बराबर यह मुतालिबा रहा है कि वह पहाडी इलाका जो हिमाचल प्रदेश के साथ मिलता जुलता है, वह हिमाचल प्रदेश मे शामिल किया जाय ताकि वह पूरी यूनिट फुलफ्लेज्डस्टेट बनने के काबिल बन सके। पहाडी लोगो की जो समस्याए है, वे पहाडी स्टेट मे मिलने से ही और पहाड़ी नजरिये से वहा के मसायल देखने से ही हल हो सकती है, यह उनका मुतालिबा रहा है। लेकिन इसका श्रेय सत फतेह सिह को जाना था कि उनके मुतालिबे के मुताबिक यह पहाडी हिस्सा हिमाचल प्रदेश को मिला। जब उस पंजाबी सूबा बिल पर इस सदन मे और दूसरे हाउस मे चर्चा हो रही थी तो इस वक्त हर एक सदस्य की यही राय थी कि क्योकि मौजूदा हिमाचल प्रदेश से अब उसका तकरीबन रकबा भी दोगुना होगा, आबादी भी दोगुनी होगी और इस तरह जब यह इलाका उसको दिया गया है तो उसको पूरी स्टेट का स्टेटस भी दिया जाना लाजिमी है। लेकिन उस वक्त दुर्भाग्यवश उस तरफ तवज्जह नही हो सकी। जैसा कि कहा जाता है, यूनियन टेरीट्रीज होम मिनिस्ट्री की एक जागीर के तरीके पर होती है उस वक्त उस पर पूरी तरह से गौर न करते हुये उस मसले को टाल दिया गया। हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वह इससे बहुत दुखी है और उसको बहुत रंजिश है इस बात की कि उसका इतना रकबा और आबादी बढाने के बावजूद भी उसको पूरी स्टेट का दर्जा नही दिया गया है। कारण इसमे यह बतलाया जाता है कि वह बैकवर्ड इलाका है और उसको केन्द्र सरकार की तरफ से काफी पैसा उसके डेवलपमेट के वास्ते दिया जा रहा है। मै इस मामले मे आपको

श्री शिवानन्द रमौल]

सूचना के लिये और हाउस की सूचना के लिये यह अर्ज करना मुनासिब समझूगा कि आज कोनसी स्टेट ऐसी है जिसका केन्द्र सरकार डेवलपमेंट के कामो के लिये कर्जा या सबसीडी नही दे रही है । इसके साथ साथ जो सेंट्रल टैक्सेज हे जिनमे हिमाचल प्रदेश का हिस्सा होना चाहिये था, वह हिस्सा चूकि वह यूनियन टेरीट्री है इस वजह से नही दिया जा रहा है । इस वक्त हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार यह कोशिश कर रही है कि आत्मनिर्भर होने के लिये वह साधन जुटाए और पाच दस साल के अर्से मे उसकी रेवेन्यु इतनी बढ जाय कि वह सेल्फसपोर्टिग हो सके और यूनियन टेरीटरी की जो लानत है उससे वह बाहर निकल सके । इसके लिये वहा जगलो को लगाया जा रहा है, पौधे लगाये जा रहे हे और उनको बढावा दिया जा रहा है । वहा जो नदी नाले है उनसे बिजली पैदा करने की स्कीमे चल रही है । आर्चर्ड या सेब वगैरह के बगीचे लगाने के लिय भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उनकी बढोतरी होती चली जा रही है। इसका मतलब यह है कि पाच सात साल के अर्से मे हमारा रेवेन्यु इतनी हो जाने की आशा है कि हम आत्म निभर हो जायेगे । जिस वक्त हमारी यह बिजली की स्कीमे कम्प्लीट हो जायगी, उस वक्त हम न सिर्फ आत्मनिर्भर ही होगे बल्कि केन्द्र सरकार और मुल्क को भी मदद देने के काबिल हो जायेगे ।

हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज्ड स्टेट का स्टेट्स देने की इस वक्त जो जरूरत महसूस की जा रही है, उसका कारण यह है कि यूनियन टेरीटरी होने के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट का कदम कदम पर उसमे दखल होता है। चूकि बैकवर्ड एरिया उसको कहा जाता है, इस लिये वहा की जो मिनिस्ट्री है उसको इतना जिम्मेदार नही समझा जाता जितना पूरी दज वाली स्टेट्स मे मिनिस्ट्रीज को समझा जाता है । कारण यह है कि वह यूनियन टेरीटरी की मिनिस्ट्री है और दूसरी फुल फलेज्ड स्टेट्स की मिनिस्ट्रीज है । यह ऐसी बात है जो मेरी समझ मे किसी भी सज्जन की समझ मे, आना मुश्किल है कि जहा यूनियन टेरीटरी है वहा की मिनिस्ट्री इतनी काबिल नही हो सकती, इतनी विश्वास की पात्र नही हो सकती कि उसको अपना काम चलाने के लिये खुली छुट्टी मिल सके । आज हालत यह है कि अगर हिमाचल प्रदेश मे कोई आफिसर रिटायर होता है, उसके बजाय कोई दूसरा आफिसर रखने की जरूरत होती है, तो बगैर होम मिनिस्ट्री की रजामन्दी के या उसकी ऐप्रूवल के बिना वहा पर कोई आफिसर नही रखा जा सकता है । लोकल हालात के मुताबिक अगर वहा की गवर्नमेंट के पास कोई बेहतर आदमी भी हो तो उसको वह ले नही सकती जब तक कि केन्द्र सरकार की मजूरी उसके लिये न मिल जाय या वह अपना आदमी न भेजे । यहा से कैसे आदमी जाते है, इसका यूनियन टेरीटरीज को काफी तजुर्बा है । अव्वल तो जो लोग यहा से जाते है वे कुछ मखसूस खयालात ले कर यहा से जाते है । दूसरे मैदानी हिस्से के लोग यहा से जाते है जिन के लिये वहा पहाड मे चलना फिरना, वहा काम करना और खास कर वहा की आबहवा मे काम करना बडा मुश्किल होता है और उसका नतीजा यह होता है कि यह कोशिश करते है कि जो ईजी स्टेशन है, महज उन पर उनको पोस्ट किया जाय और इसके लिये वे इधर उधर से प्रेशर भी डालते है । तो इन सारी चीजो को मद्देनजर रख कर मैं यह अर्ज करूगा कि आबादी के लिहाज से, एरिया के लिहाज से और जो अपने डेवलपमेट के साधन वे जुटा रहे है उनके लिहाज से हिमाचल प्रदेश का यह हक बनता है कि यह माननीय सदन और केन्द्र सरकार इस बात पर जल्दी विचार करे और उसको फुल फलेज्ड स्टेट का स्टेटस दे ताकि वहा की गवर्नमेंट आजाद हो कर, बगैर बाहरीदखल

के अपना काम चला सके और उस पहाड़ी इलाके को पूरी तरक्की दे सके ।

श्री बी० एन० मंडल (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का जो भाषण हुआ है, उसमे जो अंग्रेजी भाषा मे वे बोले है इसके लिए मुझे सख्त अफसोस है । बावजूद इस बात के कि हर बार इसके लिए विरोध होता है, फिर भी राष्ट्रपति का जो भाषण होता है, अंग्रेजी मे ही होता है, हमारे सविधान के खिलाफ ही उनका यह आचरण होता है । सविधान मे लिखा हुआ है कि यहा की राजभाषा हिन्दी है, दिनोंदिन अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी आवे । आज 15 बरस से ज्यादा हो गया है, फिर भी राष्ट्रपति के जरिए जो भाषण होता है वह हिन्दी मे नही होता है । यह स्थिति अत्यंत ही चिन्तनीय है ।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं और जो राष्ट्रपति के भाषण मे रहनी चाहिए थी वह यह है कि अनेक राज्यों मे जो गैरकाग्रेसी सरकारें कायम हुई हैं उनका स्वागत होना चाहिए था साफ तरीके से । वह उस तरीके से राष्ट्रपति के भाषण मे नही हुआ है । एक और बात की ओर भी राष्ट्रपति के भाषण में ध्यान दिलाया जाना चाहिए था कि देश मे जो चौथा चुनाव हुआ है उसके जरिए देश का जनतंत्र बलशाली हुआ है । एक तरफ तो उस समय की शासक पार्टी, काग्रेस पार्टी, के लोग बहुत दिन सत्ता में रहने के बाद गलत रास्ते पर चल रहे थे, जिसका नतीजा हो रहा था भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती, पक्षपात का बहुत बोलबाला । इस चुनाव ने उनका वह जो रवैया था उस रवैये पर रोक लगा दी है । इससे जनतंत्र बलशाली हुआ है । दूसरी ओर 20 बरस तक जो विपक्षी पार्टिया शासन में नहीं आ रही थीं और जो उनका कार्यक्रम था उसे सरकार मे रहकर अमल में लाने का मौका नहीं आ रहा था, इसके अलावा जो सरकारी पार्टी की ओर से ज्यादती हो रही थी उसका भी विरोध वे सफलतापूर्वक नही कर पा रही थी और इनके कारण जो निराशा उनमे हो रही थी वह भी इस आम चुनाव के जरिए दूर हुई है । आज देश के जनतंत्र मे एक तरफ तो पुरानी शासक पार्टी अपनी ठीक जगह पर आ गई है और विरोधी पार्टी भी जिनमे हीन भावना आ रही थी ठीक जगह पर आ रही है और दोनों यह समझने लगी हैं कि यह हमारा देश है और इसका इन्तजाम हम सब लोगो को मिल कर करना है । यह स्थिति चौथे चुनाव ने लाई है । इस बात का स्पष्ट वर्णन होना चाहिये था राष्ट्रपति के भाषण में, जो नही हुआ है ।

राष्ट्रपति के भाषण मे बिहार में जो अकाल की स्थिति है उसका भी जिक्र साफ तरीके से होना चाहिए था जो नही हो पाया है । गत सत्र में बिहार के बारे में हमने कहा था कि पलामू जिले मे और गया जिले में अकाल की ऐसी स्थिति है कि लोग भूखों मर रहे है, लोगों को काम नही मिल रहा है । ऐसा देखने मे और सुनने मे आया कि अनेक गैरसरकारी रिलीफ कमेटियां वहां पर काम कर रही है । फिर भी जो खबर अखबार में आ रही है हाल मे उससे मालूम होता है कि अभी भी वहा लोगो को बहुत कष्ट है, लोग पीले पड गए है, कितने मरे है, पशु जो उनको चारा नही मिलता है और पानी की भी वहां पर कमी है । इस तरह की खबर अभी भी आती है ।

हाल में बिहार में जो गैरकाग्रेसी मंत्रिमंडल बना है उसके मुख्य मंत्री और एक दूसरे मंत्री दिल्ली आए थे । उन्होंने यहा प्रधान मंत्री को कहा था कि बिहार को कम से कम चार लाख टन चावल की जरूरत है प्रति महीने आज की अकाल की स्थिति को सम्भालने के लिए, लेकिन केन्द्र की ओर से उनको कहा गया कि ऐसी बात संभव नही हो सकती है ।

[श्री बी० एन० मंडल]

अगर केन्द्र इस स्थिति को नहीं सम्भाल सकता है जबकि देश में कहीं अकाल हो और लोग भूखों मर रहे हों तो साफ साफ केन्द्र को कहना चाहिए कि तुम्हारा जो प्राविन्स है उस प्राविन्स की बागडोर अपने हाथ में लो, हमसे काम नहीं सम्भलेगा; न कि उनको घपले में रख कर वहां लोगों को मरने दिया जाय। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। उन लोगों ने यह भी कहा प्रधान मंत्री से कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित कर दिया जाय, लेकिन प्रधान मंत्री ने कहा कि अगर ऐसी बात होगी तो हिन्दुस्तान की नाक कट जायगी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। इसलिए वे राजी नहीं हुई। इस सबका नतीजा यह हुआ कि आज बिहार का आदमी भूखों मर रहा है और जो होना चाहिए था वह बात नहीं हो रही है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले कि बिहार की जनता को इस संकट मे वह खिला सकती है। अगर खिला सकती है तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले; नहीं ले सकती तो साफ साफ कह दे कि बिहार के लिए हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, बिहार के लोग खुद अपने मे इन्तजाम करें। तब इसकी जिम्मेदारी वे लेंगे।

श्री चित्त बासु (पश्चिमी बंगाल): बगावत करो।

श्री बी० एन० मंडल: दूसरी बात। जो देश मे अन्न की कमी है वह आज की कमी नहीं है। लड़ाई के जमाने में जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसी जमाने से अन्न की कमी होती आई है। बराबर कहा जाता रहा है कि अन्न की कमी दूर होगी। लेकिन दूर नहीं हुई है। मुझे ऐसा भी मालूम पड़ता है कि आज हिन्दुस्तान जो स्वतंत्र हुआ है, हिन्दुस्तान में समाजवादी नीति की ओर जाने का ख्याल पैदा हुआ शायद इस ख्याल को रोकने के लिए और देश समाजवादी रास्ते पर न जाये इसके लिये यहां के जो पूंजीपति हैं, यहां के जो कुछ बड़े आफिसर्स है, शासक पार्टी के कुछ लोग है या दूसरे देशों की जो कुछ सरकारें हैं इन सभी लोगों ने मिलकर इस तरह का षड़यंत्र किया है कि हिन्दुस्तान इतना कमजोर हो जाय, हिन्दुस्तान अपने आपको न चला सके, वह दूसरे देशों के निर्देशन पर चले। हिन्दुस्तान की आज जो कई कमजोरियां हैं, आर्थिक कमजोरी या अन्न की ओर दीगर कमजोरी है उसके पीछे मुझे इस षड्यंत्र का शुबहा होता है। इसलिए मै चाहता हूं कि सरकार इन सारी बातों को सामने रख कर इस बात की जांच कराए। संविधान मे कानून है कि सरकार ऐसी जांच करा सकती है। मै चाहता हूं कि उसके जरिए इन बातों की जांच हो।

खाद्य की समस्या है। इसको हल करने के लिए सब पार्टियों को मिलाकर एक संगठन बनाया जाय और उस संगठन की ओर से एक तरफ अन्न की समस्या कैसे हल की जा सकती है उसका उपाय निकाला जाय और दूसरी तरफ इस बात की भी जाच कराई जाय कि क्या हिन्दुस्तान की सरकार ने भूतकाल में या इसके कुछ लोगों ने इस तरह का षड्यंत्र किया है या नहीं किया है कि जिससे यहा की पैदावार न बढ़ पाए और अगर पैदावार बढ़े भी तो उसका वितरण लोगों में ठीक से न हो पाए जिससे देश में तकलीफ हो और देश की सरकार परेशान हो और इस तरीके से जो दूसरे पूंजीवादी देश हैं उनके चंगुल में देश फंसा रहे। इस तरह की कोई बात हुई है या नहीं हुई है इस बात की जांच होनी चाहिए।

एक दूसरी बात जो हाल में अखबार में हमने पढ़ी है वह है सी० आई० ए० के बारे में यानी अमरीका का जो सी० आई० ए० है उसकी कार्यवाही चल रही है या दूसरी विदेशी सरकारों की ओर से जो कार्यवाही चल रही है, जासूसी की कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत लोगों को रुपया देकर, इस देश के लोगों को डिमारलाइज़ कर, अपने देश ले जाकर या

दूसरी तरह से उनको डिमारलाइज कर हिन्दुस्तान को सरकार की जो पालिसी है हिन्दुस्तान के पक्ष मे उस पालिसी को प्रभावित करने की कोशिश होती है । इसकी भी जांच सरकार को करानी चाहिए। इन सारी बातों की चर्चा राष्ट्रपति के भाषण मे होनी चाहिए थी जो नही हो पाई है ।

तीसरी बात जिसकी ओर मैं इस हाउस का ध्यान खीचना चाहता हू वह यह है कि आज तक राष्ट्रपति का जो स्थान सविधान में है उसको देखने से मालूम पडता है कि जो शासन चल रहा है उसमें वे दखल दे सकते है । लेकिन ऐसा कंवेंशन यहा पर बनाने की कोशिश हुई है कि जो शासन देश का चल रहा है उसमे राष्ट्रपति दखल नही दे सकता है। इस तरह का कवेशन बनाने की कोशिश की गई है जैसा कि विलायत में है। ...मझता हू कि जो हिन्दुस्तान का संविधान है उस संविधान के जो शब्द हैं उन शब्दों से राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर देश के शासन में गडबडी देखें तो वह उसमे बीच मे इंटरवीन कर सकते हैं, वह रोक सकते है और दूसरे तरीके से शासन चलाने के लिये मंत्रिमडल को मजबूर कर सकते है। यह पावर इनको है ऐसा मैं समझता हूं। इस संबंध में जो पोजीशन हो उस पोजीशन की भी जाच होनी चाहिये लेकिन मेरा अपना मत है कि उनको ऐसा अधिकार है। यह कैसे करना चाहिये । एक तरफ तो मत्रिमंडल है जिस मंत्रिमंडल को पालियामेट का और राष्ट्रपति का विश्वास रखना है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति है जो कि अगर गड़बडी करेगे तो उनको भी निकालने की कार्यवाही पालियामेंट में हो सकती है, इसलिये दोनो के ऊपर चैक है। विलायत का जो राजा है वह राज्य का हैड भी है, वह राजा चुना नही जाता है लेकिन हिन्दुस्तान का जो राष्ट्रपति होता है वह चुना हुआ होता है। इसलिये यह राष्ट्रपति सिर्फ मूर्ति की नाईं शासन में न रहे बल्कि वह कारगर होकर रहे। ऐसा मै चाहता हूं कि अगर कोई पार्टी शासन में आकर गड़बड़ी करना चाहती है और राष्ट्रपति इस बात से कविंस हो कि इस पार्टी के जरिये गडबड़ हो रही है तो राष्ट्रपति उसको रोकने की कोशिश करे और रोकने की कोशिश करने के सिलसिले मे जो वह कार्यवाही करे उस कार्यवाही के लिये मत्रिमडल की ओर से या प्रधान मत्री की ओर से अगर यह कहा जाय कि मेरी सलाह के बिना आप कोई शासन का काम नही कर सकते है तो वैसे समय में उनकी बात को काट करके उनको कुछ करना चाहिये और इसका जो कासीक्वेंस होगा वह हो, अगर वह गल्ती करेंगे तो उनके ऊपर भी पालियामेट मे निकालने की कोशिश होगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का जो राष्ट्रपति हो वह इफेक्टिव राष्ट्रपति हो न कि विलायत जैसा मूर्ति की नाईं सिर्फ देखने वाला कास्टीट्युशनल राष्ट्रपति हो। उस तरह का राष्ट्रपति हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति नही हो, यह मैं चाहता हू ।

तीसरी बात मै प्लान के बारे में कहना चाहता हू । यह प्लान फेल हो गया है, इसकी नीति फेल कर गई है फिर भी जो प्लान चलाया जा रहा है और जो प्लान चलने को है वह उसी नीति के आधार पर चलेगा। उसमे क्या खराबी है इसको मैने सोच कर देखा है। इसमे खराबी यह है कि अभी का जो प्लान है वह प्लान सिर्फ ऐसे लोगो को फायदा पहुचाने के लिये है जो कि देश में अल्पसख्यक है । देश मे 50 करोड़ आदमी हैं उनमे जो एक प्रतिशत आदमी हैं उनके लिये यह प्लान चलाया जाता है। इसलिये यह प्लान जो अभी थोडे लोगो का अभिमुख है उसको अधिक लोगों

[श्री बी० एन० मंडल]

का बहुमत का अभिमुख बनना है और उसको ऐसा बनाने के सिलसिले में सारी बातों में इसकी जो भी नीतियां हैं उन नीतियों में परिवर्तन करना जरूरी है लेकिन ऐसा हमको मालूम पड़ता है कि आज का जो समाज है उस समाज में जिन लोगों की चलती बनती है पार्लियामेंट में भी जिन लोगों की चलती बनती है या अखबार के क्षेत्र में जिन लोगों की चलती बनती है जो समाज में बोलने वाले आदमी हैं जिनकी चलती बनती है इन लोगों का जो स्वार्थ है वही स्वार्थ आज प्लान को ठीक रास्ते पर आने नही देता है, उसकी ठीक तरह से समालोचना नहीं होती है क्योंकि इस प्लान के जरिये सबसे बेसी दुख उन लोगों को होता है जो कि पुराने जमाने से गरीबी का जीवन बिता रहे हैं, जोकि पुराने जमाने से पिछड़े हुये हैं और दुखी हैं। इस प्लान के चलने के सिलसिले में जो तकलीफ है वह उन्हीं लोगों को है लेकिन वह उतना बोलने वाले नहीं हैं और यही कारण है कि जो बोलने वाले हैं उनके लिये तो थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है और इसीलिये इस प्लान के चलने के सिलसिले में जो हल्ला इस देश में होना चाहिये था वह नहीं होने पाता। कांग्रेसी शासन ने जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी की उस गड़बड़ी का जो नतीजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ा है वह उसे जानते होंगे। वह जानते है कि चुनाव के जमाने में जहां कही जाते थे वहां क्या हालत थी। एक जगह तो सुना कि एक उम्मीदवार के सिर पर जो बिहार राज्य का एक मिनिस्टर था, जो चाय का गर्म पानी है वह दे दिया गया, किसी दूसरी जगह एक केन्द्रीय मंत्री का कपड़ा फाड़ दिया गया और दूसरी दूसरी जगह भी कितने ही दूसरे कांग्रेसियों की कितनी तरह की बेइज्जती हुई। आज हिन्दुस्तान के लोगों में जागृति आ गई है इस देश को, जनतंत्र को चलाने के लिये। अब जनता उठ कर के अपने हाथ में कुछ अख्तियार लेना चाहती है। हम अच्छा नही समझते कि हिंसापूर्ण ढंग से वह अख्तियार ले किन्तु वह अख्तियार लेकर जनतंत्र को ठीक रास्ते पर रखने की कोशिश कर रही है यह मैं समझता हूं कि देश के लिये एक अच्छी बात हो रही है।

इसलिये मैं चाहता था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो नई भावना, जो नया समय, जो नई परिस्थिति आई है उसकी झलक रहती किन्तु वह झलक उसमें नहीं आई है। बस इतनी बात कह कर मैं बैठता हूं।

SHRI K. P. MALLIKARJUNUDU (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, We are meeting here after the fourth General Election which has changed the political image of India to a certain extent. We have seen that the Congress Party which brought us independence and which has given us stability of administration has come out with a reduced strength and the non-Congress parties have emerged in greater numbers. It has been stated that this is a healthy sign of democracy and is a vindication of the federal structure of our polity. It is no doubt a good thing that in different States we see governments of different complexions. To my mind it looks like a multi-coloured fabric. It is no doubt true that different colours add to and enhance the lustre of the fabric, provided they are not incongruous.

I am glad, as I have already stated, that in different States we find governments of different complexions. But I am sorry to state, Mr. Vice-Chairman that I see distant glimpses of certain tendencies which are of a centrifugal character and which, if allowed to grow and develop, are likely to endanger the integrity and stability of India. An attempt is being made to build up a sort of old-fashioned rela-

tionship of the mother-in-law and the sons-in-law between the Centre and the States in which the sons-in-law try to extract as much as possible from the mother-in-law. I hope and trust that the States would behave in a more responsible manner.

I can understand their desire to have more funds. I can understand and appreciate their desire for more autonomus powers. But what I want them to see is that they should realise that they are part and parcel of a constituent Union and their welfare and interests are bound up with the welfare and the interests of the Union as a whole. I pray to God that he may inspire all the States with a sense of national pride, national purpose and national solidarity.

Coming to the Address given by our President, I would like to say one or two things without covering the entire ground. The President, in my opinion, has rightly emphasised the paramount importance of the economic field. He has laid down four objectives before the Government which are very important in the economic sphere and in which direction the Government propose to adopt certain measures. Of course of all the problems that confront us to day, the most important problem is the food problem. As some of the Opposition Members pointed out, it is not as if the Government was sleeping over this problem but we find one thing, namely, that the efforts so far made on the food front are not sufficient to meet the situation. If I am allowed to quote certain figures, I would say that so far as agricultural production of foodgrains is concerned, the figures are these: In 1950-51 we produced 54.92 million tonnes of foodgrains and in he peak year of 1964-65, we see that the production was 88.95 million tonnes but unfortunately owing to the drought conditions in two successive years, we find a shortfall in the production of foodgrains and the Fourth Plan rightly lays stress on the fact that we should be able to produce 120 million tonnes of foodgrains by the end of the Fourth Plan and the Government mentions various measures to attain this physical target. The measures are, the introduction of high-yielding varieties of foodgrains, improved seeds, increased supply of credit, provision of irrigational facilities, exploitation of underground water by energising the wells, etc. These are some of the measures that the Government have been adopting and will be adopting but I would say that whatever may be the importance of these measures, I would emphasise that fertiliser is the most important thing in the matter of food production. I stated on the floor of this House previously and I state here and now that fertiliser is the kingpin of increased agricultural production. If we look at the figures of indigenous production of fertilisers, we cut a very sorry figure. Our installed capacity is 5.86,000 tonnes but we are able to produce only 2,40,000 tonnes of fertilisers. Our estimate by the end of the Fourth Plan in order to attain the target of 120 million tonnes of foodgrains is that we need 3,070,000 tonnes of fertilisers. Where is the possibility of indigenous production in this matter and the Government hopes to set up fertiliser factories which, according to them, would yield 16,30,000 tonnes by the end of the Fourth Plan?

[THE DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*]

Even then it leads to a deficit of 15 lakh tonnes. Unless the Government takes vigorous steps to set up fertiliser factories, it is not possible to attain the physical target of 120 million tonnes. I calculated the requirements of our people of 500 millions on the basis of 16 ounces a day. On that basis we require 90 million tonnes of foodgrains and our present production, according to the Government estimates, for the year 1966-67 is about 77 million tonnes. So we have to make up the leeway of 18 million tonnes which is roughly 25 per cent. of our production. I think it is not impossible for us, if we apply

[Shri K. P. Mallikarjunudu.]

our minds to the making up of this 25 per cent. deficiency. So I would like the Government to establish more fertiliser factories, to take every possible measure to see that more fertiliser factories are established in India either in the public sector or in the private sector and see that adequate fertilisers are made available to our farmers.

Then in the matter of fertilisers, I would say one thing from my experience. When fertilisers are made available and when they are meant to be supplied to the farmers for agricultural produce, they are being diverted to commercial crops. That contingency has to be avoided and the Government should take proper measures to see that the fertilisers meant for agricultural production should go into that sector and they should not be diverted to the commercial crops.

One thing more about food. In the matter of distribution of food, I would lay stress on the recommendations of the Foodgrains Policy Committee and the Government should take steps to establish a National Food Council which is the only proper answer for a proper distribution of foodgrains.

Coming to the question of rise in prices which is next in importance to that of food, I would say that apart from the shortfall in production of commodities, there is the monetary factor which went into the rise in prices. But for the deficit financing undertaken by the Government during the three Plans I have no doubt that the prices would not have risen to the level to which they have now risen. With your permission I can mention that the total deficit financing during the three Plans amounted to Rs. 2,574 crores. It is a staggering figure and if we inject so much money into circulation, if we resort to the printing press and thus increase the circulation of money, it is an undeniable fact that the prices are bound to rise. So according to me, and I believe according to most of the economists, it is the deficit financing that largely contributed to the present rise in the prices. So if we want to cry a halt to this, if we want to hold the price line, what has to be done is that deficit financing should be avoided once and for all and unless that is done I do not think it is possible to control the prices.

Another suggestion is, the Government should stop all non-productive expenditure except in relation to the Defence of India and security. Of course a certain amount of non-productive expenditure is necessary and unavoidable in relation to Defence and security but in regard to other matters, it is absolutely obligatory on the part of the Government to cut down all non-productive expenditure. Besides that, I would like the Government to effect economies in their expenditure as far as possiible. By these methods I think the Government can hold the price line, even though I believe that the final answer for the rise in prices is increase in production of essential commodities.

One thing I would like to mention is that the President's Address should have mentioned as the fifth objective the restoration of the balance of payments position. The President has only mentioned four objectives. I wish he had included another, a fifth objective, namely, restoration of the balance of payments position. Since my time is up, I do not want to expatiate on it and I would content myself with saying that it is one of the most important things, the restoration of the balance of payments position, for our economy at the present time.

Lastly, I would like to refer to the Rajasthan affair. Much had been said from the opposition side, namely, that the Governor of Rajasthan acted improperly and unconstitutionally. I am not going into the merits of the case, nor do I wish to express any opinion on the political propriety of the matter. But on the constitutional propriety of the matter I would like to mention one point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think you must now wind up.

SHRI K. P. MALLIKARJUNUDU: Just one minute.

I would refer the hon. Members to article 163, clause (2), wherein the Governor enjoyed powers of absolute discretion. This article reads:

"If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required *to act in his dicretion, the decision* of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion."

So he is vested with absolute discretion, which discretion cannot be questioned either in a court of law or elsewhere.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What you are saying is not so much relevant now.

SHRI K. P. MALLIKARJUNUDU: So I would submit that what the Governor did is constitutionally correct and proper.

With these few words I support the Motion of Thanks.

श्री जगत नारायण (हरियाणा) : मेडम डिप्टी चेयरमैन, मैंने इस एड्रेस को सेन्ट्रल हाल में बड़ी गौर से सुना और इसके बाद एक दो दफा गौर से पढ़ा भी। प्रेसीडेंट अपने इस एड्रेस में सरकार के पिछले कामों और कामयाबियों का बयान करते हैं और अपनी कारगुजारियों को डिफेन्ड करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने इस एड्रेस के जरिये प्रधान के मारफत जो कुछ पेश किया है वह एक पूअर डिफेन्स है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन में कांग्रेस को जो शिकस्त हुई है उससे उसने कुछ भी सबक हासिल करने की कोशिश नहीं की। मुझे पंजाब और हरियाना में कम से कम 50, 60 कांस्टीट्यूएंसी में इलेक्शन के दौरान जाने का मौका मिला था। मैंने 150 बार लैक्चर दिये और वोटरों से मिला। मुझे प्राइवेट मीटिंग भी एड्रेस करने का मौका मिला। मुझे बाकी जगहों के बारे में तो मालूम नहीं है लेकिन मुझे दो सूबाजात का इल्म है कि वहां पर कांग्रेस के हारने की वजह यह थी कि इलैक्शन के पहले पंजाब में रुपये का डेढ़ किलो आटा बिक रहा था जबकि पंजाब हिन्दुस्तान की ग्रेनरी कहलाई जाती है। पंजाब में 56 रुपया क्विन्टल पर गन्दम बिकी थी और वहा से हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों को इस भाव गई थी। यह भाव उस समय थे जब कि गन्दम पहले पहल मार्केट में आई थी। जिस सूबे में 56 रुपया क्विन्टल गन्दम बिकी और दूसरे सूबों को दी, वही गन्दम इलैक्शन के वक्त 130 रुपया क्विन्टल लोगों को खाने के लिये दी गई। इसी से आप अन्दाजा कर सकते हैं कि वहां पर लोग कांग्रेस को किस तरह से वोट दे सकते थे। मुझे दुख है कि कांग्रेस के नेताओं ने और हमारी सरकार ने अभी तक इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। तो मैं बड़े अदब के साथ उनकी खिदमत में कहना चाहता हूं कि जहां तक अनाज का सवाल है अनाज हमारे देश में थोड़ा तो जरूर कम पड़ता है जिसकी वजह से हमें बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है। वजीर साहब ने हमारे पास एक किताब सप्लाई की है जिसका नाम "Review of the Food and Scarcity Situation in India" है और यह हमको कल ही मिली है। अगर आप इसके पन्ने पलट उलट कर देखेंगे तो आप पायेंगे कि पिछले छः सालों में हिन्दुस्तान ने 80 मिलियन टन यानी 8 करोड़ टन अनाज पैदा किया। किसी साल उसने 75 मिलियन टन पैदा किया, किसी साल उसने 73 मिलियन टन पैदा किया और किसी साल 69 मिलियन टन अनाज

[श्री जगत नारायण]

पैदा किया। इस सारे हिसाब को मिलाकर औसतन करीब 80 मिलियन टन यानी 8 करोड़ टन साल में पड़ता है। एक टन में एक हजार किलोग्राम होते है। अगर आप सारे को जरब भी करें और एक आदमी को एक दिन में आधा किलो खाना मिले तो यह सारा अनाज जो 80 मिलियन टन होता है वह 44 करोड़ इन्सानों के लिये काफी है। वजीर साहब बेशक हिसाब लगा ले कि आधा किलो अगर एक आदमी को एक दिन में दिया जायेगा तो 44 करोड़ आदमियों को दो दफा खाना आसानी के साथ दिया जा सकता है। इसके अलावा 8 मिलियन टन अनाज हम बाहर से मगाते हैं। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां अनाज की कमी नही है।

प्रोफ़ेसर डांडेकर, डायरेक्टर आफ गोखले इन्टीट्यूट आफ पोलिटिक्स एण्ड इकानामिक्स, पूना ने 'मेनस्ट्रीम' में एक आर्टिकल लिखा है "फूड एन्ड फ्रीडम"। मेरे पास इतना समय नही है कि मैं उसको आपके सामने पढकर सुनाऊं। इस आर्टिकल में उन्होंने दो बाते पेश की हैं। मैं वजीर साहब से अर्ज करूंगा कि वे इस आर्टिकल को पढ़ें जो कि बहुत ही थाटफुल है। उन्होंने लिखा है कि दूसरी वर्ल्ड वार तक हिन्दुस्तान दूसरे देशों को अनाज मुहैया करता था। उन्होंने लिखा है कि दूसरी लड़ाई से पहले हिन्दुस्तान में इतना अनाज होता था कि हमारे देश से अनाज बाहर जाया करता था। लेकिन सेकिन्ड वर्ल्ड वार के बाद जो हालत हुई हैं उसके बारे मे भी उन्होने डील किया है। इस बात को डील करते हुये उन्होंने दो बातो की तरफ़ तवज्जो दिलाई है। उन्होने लिखा है कि हिन्दुस्तान में अनाज काफी पैदा होता है लेकिन बात यह है कि प्रोक्योरमेंट कम होता है। उन्होंने इस किताब में खुद जनर्रल समरी करते हुए लिखा है कि क्यों अनाज कम है; उन्होंने यह लिखा है "the poor procurement performance in the States". सीधी बात यह है कि हमारे यहां प्रोक्योरमेंट बहुत कम होता है। तो मैं यह समझता हू कि अगर हमारी सरकार ज्यादा प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश करे तो फिर अनाज की कमी नही रहेगी। जो बड़े बडे व्यापारी हैं उन्होंने आज यह किया है कि वे देहातो में लैंड लार्ड से मिल गये है और उन्होने देहातों में ही अनाज को इकट्ठा कर लिया है और वहा पर स्टोर खोल दिये है। अगर देहातो से अनाज निकल आये, हमारी सरकार निकाल सके, तो हमारे देश में इतना अनाज हो जायेगा कि उसे बाहर के देशो से भी अनाज मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कहत की हालत इस समय देश में है, वह फिर नही हो सकती है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसका एक ही तरीका है और वह यह है कि हमें अनाज का ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योरमेंट करना चाहिये। मैं समझता हू कि हमारे पंजाब में एक नान कांग्रेस सरकार बनी है और वहा पर जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं वे जनरल स्पैरो है, जिन्होने पाकिस्तान की लड़ाई जीती थी। उन्होने एक ऐलान किया कि जिन लोगो ने अनाज छिपाया है वह उसको मडी में बिक्री के लिये ले आयें नही तो हम खुद इस तरह से अनाज को जब्त कर लेगे। इसलिये मैं यह कहना चाहता हू कि जब तक सरकार इस तरह स्टेट ट्रेडिग की पालिसी पर नही चलेगी तब तक हमारे यहा अनाज की समस्या हल नही हो सकती है।

आज हमारे देश के मुतल्लिक दूसरे मुल्को मे एक ऐसी भावना खड़ी हो गई है कि हमारा जो देश है वह भूखा और नगा है। हमारे देश को 1965-66 मे जो एक्सटर्नेल असिसटेस मिली है, अगर उसको आप देखे तो आपको पता चलेगा कि करीब 50 देशो ने हमको कर्जा दिया है। आज हमारी सरकार के ऊपर कितना कर्जा

है ? यह कर्जा करीब 5 खरब और 66 अरब रुपये का है और इस तरह से तीन प्लानों के लिये हमारी सरकार ने इतना कर्जा लिया है। इतना रुपया वह सूद का दे रही है। यह किताब जो मिली है उसमें एक चैप्टर है, जिसमें लिखा है कि पिछले साल अनाज की कमी की वजह से किन किन मुल्कों ने हमको मुफ्त अनाज दिया था। 40 देश ऐसे हैं जिन्होंने हमें 200 टन, 500 टन, 1500 टन, 35 हजार पौंड अनाज हमारे देश को मुफ्त भेजा। हमारी जो तस्वीर बाहर के देशों में फैली हुई है आपको इस किताब में मिल जायेगी कि किन किन मुल्कों ने हमको मुफ्त अनाज दिया है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे देश में अनाज है, अनाज के स्टोर हैं, मगर उनको निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है तो मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि वह इस बात की तरफ तवज्जो दे और छिपे हुये अनाज को निकालने की कोशिश करे।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि मैंने एक अमेंडमेंट भी दिया था कि डिवेल्युएशन के मुताल्लिक ऐड्रेस में बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है; और उसके सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि अपनी हालत इस वक्त यह है कि जब से डिवेल्युएशन हुआ है तब से हमारी ट्रेड में कोई तरक्की नहीं हुई है बल्कि तनुज्जली हुई है। हरियाना चैम्बर आफ कामर्स के जो सेक्रेट्री हैं, मिस्टर कस्तूरी लाल, उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी है और वह मैं दो मिनट में पढ़कर सुना देता हूं :

"You are well aware of the Government policies and with the devaluation of the rupee in June, 1966, the economy of the country has been shattered like anything. And you will be surprised to note that aften the devaluation, the earnings in export during the corresponding year from June 1st to December 31st 1966, has fallen by about 130 m. which is considerable. This is nothing but due to the discouraging policies of the Government regarding exports in cotton, jute-products, tea, rubber etc.

With a view to encourage the exports the Government of India had decided to reduce the export duty on cotton, cotton bagging and tea; but the same has no material effect, specially when other countries are keen competitors of India with regard to export of the above commodities.

Pakistan Government is giving subsidy to the exporters of these commodities. But the Government of India had imposed heavy export duties on these commodities, particularly on jute goods whereas the Government of Pakistan is promoting its exports in jute goods. If the same policy of the Indian Government continued for some time more, India will be out of world market in jute exports which is the most sterling earning commodity in the Indian economy and we can say that jute export goods are the backbone of India in earning of foreign exchange."

यह उनकी एक चिट्ठी है और मैं चाहूंगा कि वजीर साहब इसको नोट करें कि वाक़ई जो उन्होंने लिखा है वह दुरुस्त है या नहीं है और वाक़ई इस ढंग से हमारी एक्सपोर्ट में कमी हो रही है या नहीं हो रही है। इस सिलसिले में हिन्दुस्तान टाइम्स में भी छपा था, लेकिन मैं वह पढ़ना नहीं चाहता।

आज यहा सुबह हाउस में कहा गया कि बिहार में फेमीन ही नहीं है, हम मानने को तैयार ही नहीं है कि वहां लोग भूखों मर रहे हैं। यह मेरे पास एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का सर्कुलर है 20 तारीख का नम्बर 30 इसमें स्वेडन के अखबार से उन्होंने यह कटिंग भेजी है। इसमें यह लिखा है :

"The two Indian States which have been hardest hit by the drought this year are Bihar and Uttar Pradesh, which are situated between West Pakistan and East Pakistan. About 80 million people are existing

[श्री जगत नारायण]

here on the border of starvation. Foreign newspaper representatives who have visited Bihar and Uttar Pradesh say that the people eat anything that can be chewed, the bark of trees, roots of all kinds, wild berries and insects are dried, crushed and baked into bread."

यह वहां के एक अखबार ने हमारे हिन्दुस्तान की तस्वीर दी है, दो सूबाजात की।

(*Time bell rings*)

चूंकि आपने घंटी बजा दी है, इस लिये मैं जल्दी में यह और बता दूं कि आगे जाकर उन्होने यह लिखा है कि स्केलिटन तरीके के लोग इन दो सूबाजात में इधर उधर घूम फिर रहे है । बाहर के देशो में यह हमारा प्रोपेगंडा हो रहा है :

"In the villages of Bihar and Uttar Pradesh, people are walking around like living corpses, with their eyes on the road, hoping that a van with food would come. Their skin is dried up, their stomach has fallen in, and their eyes hollow. They are half-dead of starvation. Many of them eat only every second or third day."

यह बाहर के अखबारों में हिन्दुस्तान के मुताल्लिक चर्चा हो रही है और मैं वजीर साहब की खिदमत मे यह कहना चाहता हू कि आज जो तस्वीर है हिन्दुस्तान की उसको वे देखने की कोशिश करे। यह किताब जो उन्होने सप्लाई की है इसमें मैं यह पढ़कर हैरान हो गया कि एक हफ्ते के लिये एक आदमी को सिर्फ डेढ़ किलो गेहू या आटा दिया गया। यह एक दिन में एक आदमी के लिये दो छटांक के करीब होता है और मेरी समझ मे नही आता है कि इतने आटे से एक आदमी किस तरह से अपना काम चलाता होगा। फिर भी यह कहा जाता है कि यहा फेमीन नही है।

मैडम, मै बहुत ज्यादा वक्त नही लूगा। सिर्फ मैं एक बात और कहना चाहता हू कि आज छोटे छोटे देशो मे भी बड़ी तरक्की हो रही है, मगर हमारा देश दूसरे देशों से कोई सबक हासिल करने की कोशिश नहीं करता। अब आप फार्मूसा या जापान को ले लीजिये। जापान में सारे इलाके के एक बटे छः हिस्से में काश्त होती है, मगर जापान के लोग एक पौंड कोई चीज बाहर से नहीं मंगवाते है। वे सारा अनाज अपने देश में पैदा करते है। हमारे देश में तीन चौथाई हिस्से में काश्त होती है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में हमें भूखा नंगा कहा जा रहा है और हम हर देश के आगे हाथ फैला रहे है।

एक बात मैं कहना चाहता हू और वह यह है कि मैंने कल छागला साहब का बयान पढ़ा। उन्होंने अपने बयान में यह कहा था कि अरब के देशो के लोग हम से इसलिये खुश होते है कि हमने इजरायल के साथ ताल्लुकात नही बढ़ाये और इसलिये हमने अरब के देशों को खुश करने की कोशिश की। मैं यह कहना चाहता हू कि पाकिस्तान के साथ जंग के समय अरब के एक भी देश ने हमारा साथ नही दिया था। लेकिन आज आप यह देखिये कि पाकिस्तान इजरायल के साथ ट्रेड कर रहा है। । तो मैं यह समझता हू कि यह जो डिफिरेंशिएट करने की हमारी सरकार की पालिसी है, यह नही होनी चाहिये। चाहे फार्मूसा हो, चाहे इजरायल हो, या कोई मुल्क हो, सब के साथ हमारे एक जैसे ताल्लुकात होने चाहिये और सबके साथ हमको ट्रेड करनी चाहिये। बस यही मुझे आपसे अर्ज करना है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Yajee. You have to be brief. Please take only ten minutes.

श्री शीलभद्र याजी : डिप्टी चेयरमैन, देवब्रत मुकर्जी ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के ज्ञापन का प्रस्ताव किया है, मै उसकी ताईद करते हुए यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो आम चुनाव हुए उसमे सतुष्टि जाहिर की है, लेकिन मै समझता हूं कि जो जमहूरियत को प्रजातंत्र को समझने वाला है, मानने वाला

है, वह उससे खुश नहीं होगा । ये जो चुनाव हुए उसका हमारे महन्त जी जो बहुत दिनों तक कांग्रेस में रहे, उन्होंने एक खाका खीचा एक नक्शा खीचा कि क्या क्या किया गया । लेकिन मेरा तो दूसरा अभियोग है । हम भी 1937 से एलेक्शन लड़ रहे हैं । पिछले चुनाव मे 12 राज्यों में हमको भी जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि किस तरह से विरोधी दल के लोगों ने और खासकर जो सांप्रदायिक हैं और जो दक्षिणपंथी है, उन्होंने उत्पात मचाया । कहीं कहीं गोली भी चली । पंजाब में एक जगह में एक एलेक्शन मीटिंग में भाषण दे रहा तो दनादन गोली भी चली, आदमी भी मरे, लेकिन मीटिंग भी चली । और इस तरह से मध्य प्रदेश में सभी जगहों मे हुआ । किस तरह से पोलिंग हुई ? राष्ट्रपति जी ने कहा महिलाएं बहुत ज्यादा तादाद में आई लेकिन मै कहता हूं कि महिलाएं नही आई, मर्द लोग महिला बन-बन कर वोट करने आए बीस-बीस बार और वोटरों को, हरिजनो को जो बैकवर्ड क्लासेज के लोग है उनको रोका गया । इस तरह से चुनाव हुआ । डेमोक्रेसी की हम दुहाई देते है खास तौर से विपक्षी दल के लोग जिन्होंने कहा कि समाजवाद बुलेट से नही बल्कि बैलेट से आएगा, लेकिन बुलेट चली, गोली भी चली, लाठी भी चली, प्राइम मिनिस्टर की नाक टूटी, दांत भी हिल गए और इस तरह से जो इलेक्शन हुआ वह देश के लिए शुभ लक्षण नही है । नतीजा क्या निकला कि जो समाजवाद को चाहने वाली पार्टी है वह तो पीछे हो गई और राइट रिएक्शन या साम्प्रदायिक सख्या और रिएक्शनरी राजा और महाराजाओ की पार्टी, महारानी की पार्टी, खासकर स्वतत्र पार्टी के लोगो की तरक्की हुई । यह देश के लिए शुभ लक्षण नही है । यह हुआ क्यो ? यह सारा हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से हुआ । हमारे सीतलवाड जी ने ठीक कहा कि लोगों में गुस्सा था । इसके अलावा खाद्य समस्या को हमारी सरकार अभी तक सुलझा नहीं सकी । वह समाजवाद की बात कहती है, संसद का प्रस्ताव है, केन्द्रीय सरकार भी कहती है कि हम समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी राज बनायेंगे, लेकिन—प्लान है, योजना है ठीक है उसके मुताबिक काम होता है—जिस रफ्तार से समाजवाद की स्थापना हो रही है उससे सैकडो बरस लग जाएगे । समाजवादी व्यवस्था बनेगी या नही बनेगी हमको इसमें सन्देह मालूम पड़ता है । यह बात सही हो या गलत लेकिन जनता जनार्दन ने सरकार को भी सबक दिया है । इसके साथ ही जो डेमोक्रेसी के मानने वाले है, पसन्द करने वाले हैं उनको सोचना है कि यह कहा तक ठीक है कि चुनाव में जोर-ज़बरदस्ती हो, गोली,लाठी चले । यह सब हमारी शासकीय पार्टी की तरफ से नही बल्कि विरोधियो की ओर से हुआ है । वोटरो को रोका गया है, हरिजनो को वंचित किया गया है, महिलाओं को जाने नही दिया गया है । इस तरह की चीज़ देश के लिए शुभ लक्षण नही है ।

राष्ट्रपति जी और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर हुई । उन्होंने कहा कि जनता की ख्वाहिश थी । जनता की बहुत कुछ ख्वाहिश नही थी लेकिन जनता की ख्वाहिश हो गई । यह बात सही है कि आम जनता मे असन्तोष है । कांग्रेस तो महान सस्था है और वह रहेगी चाहे सभी सूबो मे कांग्रेस की हुकूमत बने या न बने लेकिन इस देश में अगर कोई पार्टी समाजवाद की स्थापना कर सकती है तो कांग्रेस ही कर सकती है । ये तीन कनौजिया तेरह चूल्हे जो उधर बैठे हुए है नही कर सकते क्योंकि इनमे एकता नही है यूनिटी नही है । कहा स्वतत्र पार्टी, जनसघ और कहा समाजवादी पार्टी लेफ्ट कम्युनिस्ट और राइट कम्युनिस्ट यह सब चू-चू का मुरब्बा है । 14-14 पार्टियों की गवर्नमेंट बनी है लेकिन यह चलने वाली नही है । अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है । इसलिए सीतलवाड जी ने और

[श्री शीलभद्र याजी]

कतिपय सदस्यों ने सरकार को चेतावनी दी है खाद्य नीति के बारे मे और समाजवादी नीति के बारे मे । हमारी जो ढुलमुल नीति है उसका परित्याग करना पडेगा । इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए हमको खेद के साथ कहना पडता है कि राष्ट्रपति ने जो हमारी सरकार की मूल नीति है ससद मे बताई हुई नीति है समाजवादी राज बनाने की उसके बारे मे जिक्र तक नही किया । जब दोनो सदनो के सामने राष्ट्रपति भाषण देते है तो सरकार की जो मूल नीति है उसके बारे मे उल्लेख भी नही करते कि समाजवादी व्यस्था बनाने मे समाजवादी राज बनाने मे हमारी सरकार क्या करने जा रही है । ठीक है कि इतने बरसों के बाद हम दूसरे देशो से गल्ला नही लेगे मदद नही लेगे लेकिन इसके साथ साथ उनको बताना चाहिए था कि हमारी सरकार समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए ये-ये रास्ते लेगी ये-ये कदम उठाएगी । यह राष्ट्रपति के भाषण मे एकदम नही है । इसलिये हम सरकार को बताना चाहते है है कि काग्रेस सरकार को समाजवाद की स्थापना की नीति अपने सामने रखनी पड़ेगी । इस सदन मे और बाहर हम बारबार कहते रहे है कि अब ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है । सब लोगो की यह माग है । जनता की भी माग है वोटर की माग है कि जल्दी से जल्दी जो इस देश मे गरीबी है उस गरीबी का उन्मूलन हो । हो सकता है कि जब समाजवादी व्यवस्था कायम हो तो दल भी सहयोग करे । इसलिए सरकार की जो ढुलमुल नीति है वह समाप्त हो । समाजवाद की जो धीमी रफ्तार है उसको तेज करना पडेगा और 1970 तक इस देश मे समाजवादी रिपब्लिक बनाने की नीति सरकार को घोषित करनी चाहिए । जो सविधान है कास्टीट्यूशन है उसमें रेडीकल अमेडमेट, सशोधन करने की जरूरत है । जो कलकारखाने बेसिक इन्डस्ट्रीज है बैंक है उन सबका जल्दी जल्दी सरकार को राष्ट्रीयकरण करना चाहिए । जितने गवर्नमेट मुलाजिम है वे सब खिलाफ हो गए कि जैसे भी करो सरकार को गिराओ चूकि महगाई भत्ता नही देती । उनकी पढाई-लिखाई का इन्तजाम नही करती है । इसलिए यदि ज्यादा से ज्यादा बैंको का, कारखानो का और बाकी चीजो का समाजीकरण करेगी तो उसके पास इतना धन हो जायेगा कि उसे अमरीका के पास रूस के पास जाने की जरूरत नही रहेगी । जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा भत्ता देकर खुश कर सकती है । इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी 1970 तक इन्डिया को सोशलिस्ट रिपब्लिक डिक्लेयर करके इन सब चीजो का राष्ट्रीयकरण करने की रफ्तार तेज करनी चाहिए । वोटरों ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक आप समाजवादी व्यवस्था कायम करिए और आर्थिक दशा सुधारिए । मै काग्रेस पार्टी की बात नही कर रहा हूं हमारे हिन्दुस्तान की जो 50 करोड जनता है जो उनको दुख है तकलीफ है जो गरीबी है बेकारी है उन सब चीजो का समाधान रामबाण औषधि है समाजवादी व्यवस्था । उसके लिए हमारे राष्ट्रपति ने अपने भाषण मे कोई जिक्र नही किया । उनको जिक्र करना चाहिए था कि जल्दी से जल्दी समाजवादी व्यवस्था कायम की जाय भले ही स्वतत्र पार्टी के लोग चिल्लपो मचाते रहे । धीमी रफ्तार से चलने वाली समाजवाद की गाडी को तीव्र करना पडेगा यही हमारी सरकार से प्रार्थना है ।

श्री लोकनाथ मिश्र लोगो ने आपको वोट नही दिया इसलिए समाजवादी ढाचे की बात करते है ।

श्री शीलभद्र याजी आपको उठाकर फेक देगे ।

ALLOCATION OF TIME FOR GOVERNMENT BUSINESS

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting